(شری گنگا ریڈی)
اس بات کو سوچے اور سینچائی کے محکمے کو جو پیسہ دیا جاتا ہے اس پر کوئی سود عاید نہیں کیا جائے۔ ابھی تک ناگ ارجن ساگر، دولیشورم اور لنگ بھدر کی یوجنائیں کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں۔ چیزوں کی قیمتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے ان کی کنسٹرکشن کاسٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ لہذا میں آپ سے گذارش کرونگا کہ ان یوجناؤں کو آپ فورن کمپلیٹ کریں۔ جہاں سے میں آتا ہوں وہاں پر موجودہ حالات میں ۷۵ مواقع سیلاب ہو رہے ہیں، ۳۶ عادل آباد ضلع میں ۲۹ نظام آباد میں۔ وہاں پر دو کنالس کا پروپوزل ہے۔ میرے ضلع میں نارتھ کنال کا پروپوزل ہے۔ وہاں پر ہزاروں ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے لیکن ایک انچ کی بھی سینچائی نہیں ہو رہی ہے۔ سپیکر صاحب ہمارے ہر دیش سے ہی آئے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں۔]

MR. CHAIRMAN : The hon. Member may continue his speech tomorrow.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Thirty-third Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): Sir, I beg to present the Thirty-third Report of the Business Advisory Committee.

MR. CHAIRMAN : We will now take up the half-an-hour discussion.

---

18. 30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Hindustan Zinc Limited

श्री ओंकार लाल बोहरा (चित्तौड़गढ़): मान्यवर, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड हमारे देश का एक मात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्योग है जिसमें जस्ता और शीशा पैदा होता है, चांदी का उत्पादन होता है और बाई प्रोडक्ट के नाम पर सलफ्यूरिक ऐसिड, सुपर फ़ासफ़ेट और कैडमियम का उत्पादन होता है। 22 अक्तूबर, 1965 को यह एक प्राईवेट सेक्टर था और उस के बाद अमरजेंसी के अन्दर, डी० आई० आर० के अन्तर्गत, आवश्यक सेवाओं के अधीन समझने से पब्लिक सैक्टर में इस का हस्तान्तरण हुआ। पब्लिक सैक्टर में आने के पहले इस उद्योग की क्या स्थिति थी इस पर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर के पहले इस का 80 परसेंट काम समाप्त हो चुका था और ऐसा लगता था कि अगर पब्लिक सैक्टर के अन्दर आने के पहले यह प्राइवेट सेक्टर में रहता तो साल भर में वह अपनी पूरी कैपेसिटी में आ जाता। उन्हों ने तीन, चार करोड़ रु० की मांग की थी लेकिन किसी कारण से, अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे इस को नहीं संभाल सके। लेकिन यह खुशी की बात है कि यह पब्लिक सैक्टर में आया और ऐसे उद्योग जो राष्ट्रीय महत्व के हैं अगर पब्लिक सैक्टर में लिये जाते हैं तो उस से राष्ट्र को फ़ायदा ही होता है।

पब्लिक सैक्टर के प्रति अपनी सहानुभूति और आस्था प्रकट करते हुए मैं यह निवेदन

करना चाहता हूं कि हमने इस देश में पब्लिक सैक्टर की जो योजना बनायी है वह इसलिये नहीं बनायी है कि हमारे राष्ट्र को करोड़ों रु० का घाटा लगे। दुर्भाग्य की बात है कि आज जो पब्लिक सैक्टर में कारखाने चल रहे हैं उन की हालत यह है कि तीन, चार सौ करोड़ रु० का घाटा चल रहा है उन में और हम आंख मूंद कर इस घाटे को बर्दाश्त कर रहे हैं। हम यहां देश में समाजवादी व्यवस्था चाहते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर इस पब्लिक सैक्टर में इतना घाटा क्यों होता है। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में पब्लिक सैक्टर को आज की स्थिति में जो लाये हैं वह आफिसर्स लाये हैं जिन की पब्लिक सैक्टर में कोई दिलचस्पी नहीं है और जो नहीं समझते हैं कि पब्लिक सैक्टर का उद्देश्य देश की सम्पत्ति बढ़ाना है, देश को समृद्धिशाली बनाना है, और ऐसे वातावरण में लाना है जिस से देश की विदेशी मुद्रा बचे और इस देश का लाभ हो।

जब 80, 90 परसेंट यह कारखाना कमप्लीट हो चुका था, और अपनी पूरी कैपेसिटी पर आने वाला था और उस समय जब पटेल कारपोरेशन ने चार करोड़ रु० की मांग की थी वह नहीं मानी गयी। और आज पब्लिक सैक्टर में आने के बाद अभी तक उस में लगभग 11 करोड़ रु० खर्च हो चुका है और इस के बाद भी आज स्थिति यह है कि उस का प्रोडक्शन आधा है और कम से कम 10 लाख रु० प्रति महीने का घाटा उस में चल रहा है।

अब मैं आप के सामने दो तीन बातों का जिक्र करना चाहता हूं कि इस का उत्पादन क्यों गिरा और इस की प्लानिंग कितनी गलत है। इस का उत्पादन इसलिये गिरा कि इस के साथ साथ जो हमारी खानें थीं जावर माइन्स, जिन से जस्ता और लेड निकलता है उन का विकास साथ साथ नही किया। जहां यह जरूरी था कि हम जावर माइन्स का डेवलपमेंट करते और उस के द्वारा ज़िंक स्मैल्टर को फीडिंग देते वह हमने नहीं किया। जावर माइन्स पूरी अरावली की श्रेणी है जिस में तीन चार बड़े बड़े पहाड़ों में ज़िंक और लेड का बहुत बड़ा भंडार है। यह सौभाग्य कीबात है कि भारत में अभी तक जो स्थान मिले हैं उन में एक मात्र मेवाड़ और राजस्थान का ऐसा हिस्सा है जिस में लेड और ज़िंक और चांदी का मिश्रण पाया जाता है। पहले चांदी निकालने के लिये ज़िंक कनसेन्ट्रेट जापान भेजते थे। लेकिन पब्लिक सैक्टर को इस काम को जितनी तेजी से लेना चाहिये था वह नहीं किया, और पब्लिक अन्डरटेकिंग में आने के बाद साल भर तक सारा ध्यान नयी नियुक्तियों, नये नये बंगलों और कारों के खरीदने में लगा दिया गया और एक साल तक हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। और जो फ्रेन्च कोलेबोरेशन के अधीन समझौता हुआ था कि टैक्नीशियन्स इस प्लान्ट को बनायेंगे, वे साल भर तक नहीं आये। नवम्बर 1966 में फ्रैन्च फर्म से ऐग्रीमेंट हुआ था। एक साल तक लगभग 30 लाख रु० 30 टैक्नीशियन्स को देना पड़ गया और उस के बाद जो जनवरी 1968 के पहले सप्ताह में इस ज़िंक स्मैल्टर का काम चालू हुआ वह भी एक सस्ती पब्लिसिटी के आधार पर हुआ। उस समय तक फरनेस नहीं आयी थी लेकिन उस का काम चालू कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि जो ज़िंक कनसेन्ट्रेट प्राइवेट सैक्टर वालों का जो स्टाक में पड़ा हुआ था उस को पांच महीने के अन्दर ज़िंक स्मैल्टर को पूरी कैपेसिटी में चला कर सस्ती वाहवाही लूटने के लिये खत्म कर दिया। और उस के बाद ज़िंक कनसेन्ट्रेट का पर्याप्त स्टाक स्मेल्टर को देने के लिये नहीं बचा और कच्चे माल की कमी पड़ गई। और परिणाम यह हुआ क्यों कि उन का कोई सेल आर्गेनाइज़ेशन नहीं था, कोई बिक्री का उचित प्रबन्ध नहीं था, प्लानिंग नहीं थी, मार्केटिन्ग की व्यवस्था नहीं थी और न कोई मारकेटिंग की सर्वे थी इस कारण जो ज़िंक कनसेन्ट्रेट से ज़िंक इन्गोट्स बनाने चाहियें थे

[श्री ओंकार लाल बोहरा]

उस के बजाय ज़िक कैथोड्स का निर्माण किया गया जिस की कि देश में कोई मांग नहीं थी और ढाई करोड़ की पूंजी ब्लाक हो गई। और जब 1968 की मई में फ़रनेस लगी तो इन के पास पर्याप्त ज़िक कनसेन्ट्रेट नहीं था ज़िक इन्गोट के लिये। परिणाम स्वरूप दो महीने तक स्मैल्टर को बन्द करना पड़ा और ज़िक कैथोड्स को ज़िक इन्गोट्स में बदलना ही पड़ा जिस से लगभग 30 लाख रुपये का नुकसान हुआ। और जब कास्ट आफ़ प्रोडक्शन के बारे में संचालकों से पूछा गया तो उन्हों ने उत्तर दिया कि क्योंकि पिछली कम्पनी को मुआवज़ा देना बाकी है इसलिये अभी कास्ट आफ़ प्रोडक्शन नहीं बताया जा सकता है, कास्ट निकालना बड़ा कठिन है। प्राइवेट सैक्टर में आने के बाद 11 करोड़ रुपया लगाया गया और अभी तक इन्हें यह मालूम नहीं है कि हमारा ज़िक और सुपरफौफेसट किस कास्ट पर पड़ रहा है। इस के अलावा पांच हज़ार टन ज़िक कनसेन्ट्रेट प्राफिट पर प्राइवेट सैक्टर को बेच दिया गया जब कि इन्हें मालूम था कि आगे कठिनाई आ सकती है, कच्चे माल की कठिनाई आ सकती है तो इन्हों ने प्राइवेट कम्पनी को क्यों बेच दिया सस्ते दामों पर ? मैं चाहूंगा कि उस की छान बीन की जाय कि पांच हज़ार टन सस्ते दामों पर क्यों बेचा गया। मैं कहूंगा कि यह एक ऐसा मसला है जिस का राष्ट्रीय महत्व है। तो इन्हों ने शुरूवात की थी 100 परसेंट के आधार पर और इस बात की तारीफ़ की गई थी कि ...मैनेजमेंट ने 100 परसेंट से अधिक पर स्मेल्टर चलाया, लेकिन अब 50, 55 परसेंट पर चल रहा है क्योंकि जवार माइन्स का डेवलपमेंट न होने की वजह से ज़िक कनसेन्ट्रेट नहीं मिल रहा है कारखाने के लिये। इन का इरादा था कि हम कनाडा और अमरीका से ज़िक कनसेन्ट्रेट इम्पोर्ट करेंगे और कारखाने को चलायेंगे। लेकिन वह इम्पोर्ट भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब भारत सरकार कच्चे माल के आयात में इस औद्योगिक प्रतिष्ठान को नहीं चला पा रही है फिर विषाखापट्टम में हम एक नया स्मेल्टर लगाने के बारे में क्यों सोचते हैं, या क्यों ऐसी योजना बना रहे हैं ? यदि हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं है, पूंजी नहीं है तो आवश्यकता इस बात की है कि इसी ज़िक स्मैल्टर की क्षमता बढ़ायें। और इस के लिये यह जरूरी है कि जावर माइन्स का डेवलपमेंट करें, इन में अधिक से अधिक खुदाई का काम करें और कच्चा माल प्राप्त करें और इसी में पूंजी लगा कर इन डिपाज़िट्स का पूरा लाभ उठायें। गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के सर्वे के आधार पर मैं कह सकता हूं कि वहां पर एक लाख टन से ज़्यादा ज़िक पैदा हो सकता है, इतना वहां पर कच्चा माल पड़ा हुआ है।

इसी तरह से सौभाग्य से उदयपुर के पास राक से फ़ासफेट का भी बहुत बड़ा भंडार मिला है जो अभी हमें सल्फ्यूरिक ऐसिड को सुपर फ़ासफेट में बदलने के लिये फर्टिलाइज़र बनाने के लिये मिडिल ईस्ट से मंगाना पड़ता है। उदयपुर के आस पास कम से कम चार करोड़ टन राक फ़ासफेट का डिपाज़िट मिला है। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत अच्छा इलाका है जहां यदि हमें एक यूनिट के बजाय अगर दो, तीन यूनिट्स भी लगानी पड़ें तो लगानी चाहिये। क्षेत्रीय असंतुलन की वजह से जो आज असंतोष फैला हुआ है उस को दूर करने के लिये जरूरत इस बात की है कि जो प्राकृतिक सम्पत्ति जहां मिले वहीं नये नये कारखाने खोले जायें।

इस प्रसंग में मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर जो श्रीमिकों के स्थिति आज चल रही है उस में एक बहुत बड़ा खतरा यह है कि श्रमिकों

में बड़ा भयकर असंतोष चल रहा है। उन के साथ अन्याय हो रहा है। श्रमिकों ने इस बात की मांग की थी कि प्राइवेट सेक्टर की आर्थिक कठिनाइयां हैं इसलिये इस को पब्लिक सेक्टर में लिया जाय। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब से हमारा नया मैनेजेमेंट आया है उस की प्रवृत्ति यह है, पुराने मजदूरों को तंग करके निकाला जाये लेकिन पिछले साल से यह स्थिति है, कि वहां पर राइवल लेबर यूनियन पैदा करने में हमारे चेयरमैन और मैनेजमेंट कोशिश करते हैं। साल भर के अन्दर अगर मैनेजमेंट ने कोई प्रोडक्शन किया है तो राइवल यूनियन को तैयार करने का विचार किया है। लेकिन जावर माइन्स के उत्पादन पर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह परियोजना बहुत आगे बढ़ी होती।

आज सलीम मर्चेन्ट अवार्ड को इमप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। और मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं कि हमने इमप्लीमेंट कर दिया। तीन, चार मिनिस्टर्स केन्द्रीय सरकार के और उस के बाद 40, 50 सदस्य पार्लियामेंट के गये, उन्होंने समझाया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि श्रमिकों के साथ आज भी वही बेजा हरकतें की जा रही हैं और उन के न्यायोचित अधिकारों पर कुठाराघात करने की चेष्टा की जा रही है। अगर समाजवाद में आस्था को कायम रखना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि श्रमिकों के हितों की रक्षा किस प्रकार की जाय और ऐसे मैनेजमेंट को जो समाजवाद की आइडियालौजी में विश्वास नहीं रखता उस को हटाया जाय। वहां पर आज हालत यह है कि उस कारखानें में जहां 700 आदमी और 30 आफिसर्स होने चाहियें थे, आज 1200 आदमी तथा 80 आफिसर्स हैं। अगर इस तरह से अनापशनाप नियुक्तियां होती रहीं तो मैं समझता हूं कि हमारा सारा उद्देश्य जो राष्ट्रीय परियोजनाओं के द्वारा, पब्लिक सेक्टर के द्वारा, देश को समृद्धिशाली बनाना है वह चौपट हो जायगा।

MR. CHAIRMAN : The hon. Member may conclude.

श्री ओंकारलाल बोहरा : इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप के द्वारा मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वह इस सम्बन्ध में जो एक निश्चय हुआ था कि डेपुटेशन पर वहां कोई आदमी नहीं लिया जायगा और प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि पब्लिक सैक्टर में डेपुटेशन पर लोग नहीं लिये जाने चाहिए और योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों को लिया जाना चाहिए और जो पुराने कार्य कर रहे हों उनको मौका देना चाहिये। और जिनकी योग्यता तथा अनुभव नहीं है उन्हें नहीं लिया जाना चाहिए इस पर वह अमल करेंगे ?

MR. CHAIRMAN : His time is over. He should conclude now.

श्री ओंकारलाल बोहरा : मैं अन्तिम रूप से कहना चाहता हूँ कि यह जो भावर माईस का डेवलपमेंट है वह इसी वजह से खत्म हो रहा है क्योंकि वहां पर अनुभवी इन्जीनियरों और कार्यकुशल प्रबन्धकों की कमी है। यही हालत जिंक स्मेल्टर की भी है। मैं चाहता हूं कि इन सारे कारणों की जांच की जाय। इसके लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त कमिशन बनाया जाय जिससे यह पता चले कि यह गलतियां कहां है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है ?

एक अन्तिम वाक्य में। मैं श्रमिक लोगों की हालत के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

MR. CHAIRMAN : No, no. His time is over. Nothing will go on record.

श्री ओंकारलाल बोहरा :*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND MINES AND METALS (SHRI JAGANATH RAO): I am thankful to the hon. Member for having raised the discussion about Hidustan Zinc Limited at Udaipur. It gives me an opportunity to explain in detail the working of this smelter.

As stated by the hon. Member, this smelter was originally in the hands of the private sector. He could not run the smelter, much less develop the mines. The Government of India took over the mines sometime in October, 1965 and the company was formed in 1966. At the time when this was taken over by the Government, there were French experts engaged by the earlier owner, the private company, but those people refused to continue the work left unfinished by them. Therefore, we had to enter into a fresh agreement with them for the erection of smelter and so on. The constrution work was completed in October-November 1967. Then the smelter went into production. The rated capacity of the smelter is 18,000 tonnes per annum. It requires 2,000 tonnes of ore per day to achieve the rated capacity. It is true that the Zawar mines not having been developed earlier by the private sector company, they imported some concentrates. The ores that are being extracted per day are roughly 800 tonnes (*Interruption*) There were imported concentrates with the company's smelter which were being used. The ore that is being extracted is only 800 tonnes per day. But it requires 2,000 tonnes. The production went on. The production lowered sometime ago to 70 per cent because a large quantity of superphosphate could not be sold in the market. That was the reason why the production was lowered.

Three points have been raised. The hon. Member said that the production was going down. I have explained the reason why the production was reduced to 70 per cent of the rated capacity. Secondly, it was said that Zawar mines were not being developed. I agree that the Zawar mines could not be developed earlier. We have been told by the experts that it takes four to five years to develop a mine. Currently we are engaged in developing the Zawar mines and the other mines that have been discovered near about in Rajasthan as early as possible so that we can extract a larger quantity of ore, so that the rated capacity of 18,000 tonnes per year is doubled to 36,000 tonnes. On that score, the hon. Member or any other Member of Rajasthan need not be under any doubt or apprehension that Rajasthan is being neglected, that the smelter will not be allowed to be developed and that another smelter would be established elsewhere in the country. The demand is expected to go up to about 1,40,000 tonnes by 1973-74 The capacity in the country is only 18,000 tonnes of Hindusthan Zinc smelter, Udaipur, and 20,000 tonnes of the private sector company at Alwaye, Chemco Binani & Co. They are also going to double their capacity from 20,000 tonnes to 40,000 tonnes. In the Hindusthan Zinc smelter also, the capacity of 18,000 tonnes will be doubled to 36,000 tonnes. Thus, the total comes to 76,000 tonnes. Still we will be left with a gap of 70,000 tonnes of zinc metal. Therefore, the thinking in the Ministry was this : anyhow we are importing every year 50,000 tonnes of zinc metal at a huge cost if imported concentrated are brought, it will reduce the cost by about 35 per cent. Therefore, while agreeing to the expansion of the two existing units in the country, which would be doubled, the thinking was to establish another smelter at Visakhapatnam based on imported concentrates.

But that project is still under study. The feasibility study and the detailed project report is not yet ready. It will take about to 6 to 8 months. Then this question will come up. Therefore, there can be no doubt or apprehension in the minds of hon. Members that the Rajasthan smelter will not be attended to. The expansion has already been agreed to by the Planning Commission and provision has been made for getting the balancing equipment and also for the development of Zawar mines. The Zawar mines have to be developed, if you want the smelter to work efficiently and achieve the rated capacity. We are now currently thinking in the Ministry how best

* Not recorded.

[Shri Jaganath Rao]

and how quick we can develop the Zawar mines. We are thinking of posting a Mining Engineer who has good experience in this and also, if necessary, get foreign collaboration. As I said earlier, it takes 4 to 5 years to develop the mine. Unless the mine is developed quickly, we cannot achievethe rated capacity much less think of expanding the capacity. The hon. Member has mentioned about labour problems. Labour problems were there. There was the award by Salim Merchant. In my view the award has been implemented except that there are three individual cases pending.

SHRI ONKAR LAL BOHRA : They have not been implemented.

SHRI JAGANATH RAO : My information is subject to correction. I can say what I am briefed by the Ministry. There were three individual cases. They are also being looked into. He has given an interim award of a pay rise of Rs. 4 per month. If there is anything else, I will certainly look into it.

SHRI ONKAR LAL BOHRA : They have gone into a token strike only because of that.

SHRI JAGANATH RAO : About the token strike, I may repeat that the strike was considered to be illegal. A committee was appointed to enquire into this question. The Committee consisted of Shri Raghunath Singh, the Chairman, Shri N. K. Bhatt, M. P. and then one Shri Venkatachalam. labour officer of the Labour Ministry. They held :

> "We appreciate the management's stand in this regard and we are also unable to concede the Union's demand for any wages for the strike period. Even so, we feel that in the circumstances of the case, the workers deserve some sympathy and therefore direct that the strike period may be adjusted towards leave due to the workers, and to the extent the individual employees may not have adequate leave to their credit, the period of strike will be treated as *dies non.*"

Therefore, this has been done.

Regarding the inter-union rivalry it has also come to my notice--it is unfortunate–that both the Unions, I understand, belong to the INTUC. It is in the interests of the workers themselves to have one single union so that they can bargain more effectively. Every industry should necessarily have a trade union. I am not opposed to any trade union. Trade Unions should be there. But if inter union rivalries exist, it is not possible for us to do anything.

SHRI ONKAR LAL BOHRA : There is no rivalry.

SHRI JAGANATH RAO : Something has been said about the Chairman of the company, that he has been siding with one union or the other. I will certainly look into that question. I quite agree that no officer or Chairman of the company should interfere and take sides with one Union against the other.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : Who is responsible for this mess ?

SHRI JAGANATH RAO : There are two unions--one is Zawar Mines Mazdoor Sangh and another is Zinc Smelter Union. Both are there. I will certainly look into this. This Chairman should not have interfered. If he has done it, we will certainly advise him not to interfere.

Then he referred to one more point about the officers on deputation. Now the recent thinking of the Government is that officers on deputation should not be sent to public sector undertakings. Once they go there they have to opt whether to continue there or not within one year. Once they go, certainly they must be there till they are required. These aspects are looked into.

MR. CHAIRMAN : Shri Biswanarayan Shastri.

Only questions please no long preamble.

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur): Even supplementaries are ollowed, he Chairman should not be more strict than the Speaker.

MR. CHAIRMAN : I am not going to allow any preamble.

SHRI BISWANARAYAN SHASTRI (Lakhimpur) : Public undertakings are intended for better employment and plough-back of the benefit to the State exchequer and the employees. But unfortunately, Sir, public sector industry in our country has become some thing worse than the private sector industry in respect of security and service conditions of the employees.

May I know from the Government statement that Salim Merchant gave award on six points out of eight points, whether in respect of six points the Award has been implemented ? I want to know this. What about the remaining two points ?

Now, my second question is this : Zinc is a rare commodity. But why is it sold through a commission agent when it can be sold directly ? These are my questions.

श्री शिकरे (पंजिम) : सभापति महोदय, दो महीने पहले मुझे जोहार माइन्ज को देखने का सौभाग्य मिला था। वहां जाने के बाद मुझे ऐसा देखने को मिला कि वहां के कर्मचारियों में असन्तोष है जिसकी वजह से वहां का काम अच्छी तरह से नहीं चलता है, उत्पादन जितना होना चाहिये, उतना नहीं हो रहा है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां की परिस्थिति की कम्प्रीहेन्सिव स्टडी के लिये वह एक सर्वपक्षीय पार्लियामेंट्री कमेटी वहां भेजें। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर कुछ ऐसी चीज होती है, तो उसके मालिक लोग देखते हैं, लेकिन पब्लिक अण्डरटेकिंग में अगर कुछ ऐसी चीज होती है तो उस असन्तोष को हमें ही जरूर दूर करना चाहिये।

दूसरी बात—जब मैं वहां गया था तो मैंने वहां के कर्मचारियों से बात की थी। वहां पर इन्टक की ट्रेड यूनियन है, शायद दो ट्रेड यूनियन्ज हो सकती हैं, शायद उनमें से एक पपेट यूनियन हो सकती है। मैं चाहता हूं कि वहां की ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों और वहां के अफसरों को साथ लेकर एक कमेटी के द्वारा उनके साथ बातचीत की जाय, इसमें वे लोग अपने सजेश्चन्ज दे सकें, कठिनाइयां कहें ताकि उन सजेश्चन्ज के आधार पर ऐसा प्रयत्न किया जाय–जिसमें हमारी अण्डरटेकिंग अच्छी तरह से चल सके।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, जस्ता उद्योग को चलाने के लिये हिन्दुस्तान जिंक लि० की स्थापना की गई है, जिसके चेयरमैन के बारे में बताया गया है–स्वनामधन्य श्री रघुनाथ सिंह उस के चेयरमैन हैं, जो हमारे इस सदन के बहुत वर्षों तक सदस्य रहे हैं, कांग्रेस पार्लियामेन्ट्री पार्टी के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और उन्होंने फासिज्म के समर्थन में एक किताब भी लिखी है। जब मैं बनारस में काशी विद्यापीठ में पढ़ता था, तब मैंने उस किताब को पढ़ा था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि हिन्दुस्तान जिंक लि० के चेयरमैन श्री रघुनाथ सिंह जी सरकारी उद्योगों के खिलाफ हैं। अगर हां, तो उन्हें उस का चेयरमैन क्यों बनाया गया ?

दूसरे मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि वहां जो लेबर ट्रबुल हो रही है, मजदूरों के बीच में जो अशांति है, जो दो दल हो गए हैं, उस दलबन्दी में भी इनका हाथ है, ये वहां पर जनसंघ की यूनियन को पनपाने की कोशिश कर रहे हैं? यदि हां, तो फिर क्या सरकार ऐसे चेयरमैन को, जिनसे कि उद्योग में अशांति हो रही है, हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

SHRI S. S. KOTHARI (Mandaur) : I should like to emphasise just one important. point on the hand there has been an accumulation of stocks of zinc and also Single superphosphate and on the other, Government have been continuing to import zinc and Diammonium phosphate, spending about 12 corores every year on the import of zinc alone. Government could have saved at least 4 crores of rupees. Such imports have resulted in cut-back in production and closing down of the unit for 2 months. This has happened in the case of aluminium industry and capacitor industry also. The first part of my question is: What steps are the Government taking to reduce one-third of the imports of zinc and to reduce substatially the imports of Diammonium phosphate so that the unit can function at its full installed capacity in and also save foreign exchange ? Secondly, there has been a reduction in the production of lead and silver. Lead production has gone down from 2,515 tonnes in 1966-67 to about 1500 tonnes in 1968-69. The production of silver has gone down from 3,250 kg. in 1967-68 to 1,900 kg in 1968-69. This is a very serious situation. Instead of improvement, the production has deteriorated. Therefore, the second part of my question is : What steps are the Government taking to check this decline in the production of lead and silver ? Finally, for three years, the shareholders have been suffering. How is it that the Government have not given them any compensation ? When are they going to give it and how much ?

SHRI JAGANATH RAO : I quite agree that public sector should be model organisation and employment facilities should be fully utilised and it should be a model industry. I quite agree with that position. But this unit has gone into production only in January 1968. Only one year has passed and there are bouud to be teething troubles. Production was reduced because a large quantity of super-phosphate was lying unsold. Therefore, production was reduced to 75 per cent.

SHRI S. S. KOTHARI : Why was it unsold ?

SHRI JAGANATH RAO : Zinc superphosphate is not popular with the formers. We have taken several steps. We have met the food and Agriculture Ministry and we have met the Fertiliser Corporation. They have agreed to take huge quantities of surplus. Unsold stocks are not very high. Even Madhya Pradesh and Rajasthan have agreed not to take the super-phosphate and Government have agreed not to import any more of Diammonium phosphate so that super-phosphate available in the country with this unit and also with other units will be utilised all over the country.

About the Committee of Members of Parliament, I do not agree with the Hon. Member. As I said, this unit has gone into production only one year ago. We are trying to see how the production can be improved and how the functioning of the unit could be improved substantially.

About the recalling of the Chairman, all know that the Chairman is appointed on a tenure. I do not remember when his tenure expires. We will certainly go into the question whether his tenure shoulh be further extended or terminated.

As the Hon, Member has said the production of lead has gone down. That is true. It has gone down because the quality of ore that we are getting now is inferior.

19 hrs.

Therefore, we are not getting the same lead content in the ore. The same thing applies to silver. They are bye products of this, namely, zinc, sulphuric acid which is utilised in manufacture, super-phosphate, cadmium, silver and lead.

SHRI S. S. KOTHARI : is there coordination between production of zinc and reduction of imports ?

SHRI JAGANATH RAO : There is only one unit of zinc and lead in the country the public sector. We are trying to imporve. The demands of the country are so large that we have necessarily to import.

SHRI S. S. KOTHARI : I am talking of a co-ordinated policy.

SHRI JAGANATH RAO : Policy is there.

SHRI S. S. KOTHARI: But co-ordination is not there.

SHRI JAGANATH RAO : We are trying to increase capacity in the country so that we can reduce import.

On the issue of compensation to shareholders.........

SHRI S. S. KOTHARI: Lakhs of people are affected.

SHRI JAGANATH RAO : ......this company belonged to the Metal Corporation of India. Some compensation was originally arrived at. Then they filed a writ petition in the Supreme Court. They did not accept our terms. That petition was dismissed. Again they have gone to the Calcutta High Court. Arguments have been heard. Judgment is expected to be pronounced. So unless we know what is the compensation payable, we are not in a position to arrive at the figure. We are equally anxious that the shareholders should be paid their due.

19.02 hrs,

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Tuesday, April 1, 1969, Chaitra 11, 1891 (Saka).